

राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के लिए
एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 792/2024

1. सुमन मीना पुत्री कडूराम मीना, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी चैनपुर, करौली (राजस्थान)।
2. रिकू कुमार मीना पुत्र वोद्या राम मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वझेडा, जिला करौली (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, लोक अभियोजक के माध्यम से।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, करौली।
4. थाना प्रभारी, पुलिस थाना हिण्डौनसिटी, जिला करौली।
5. थाना प्रभारी, पुलिस थाना मासलपुर, जिला करौली।
6. कादुराम पुत्र रामधन,
7. फोरन्टि देवी पत्नी कडुराम,
8. रूपसिंह पुत्र रामधन,
9. ऋषिकेश पुत्र रामधन, प्रतिवादी क्रमांक 6 से 9, चैनपुरा, तहसील करौली, जिला करौली
10. कल्ला पुत्र चिरंजी, निवासी झाड़ोली, तहसील बावनवास, जिला गंगानगर सिटी

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए	:	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह श्री सुखदेव सिंह सोलंकी श्री चित्रांक शर्मा श्री मोहरपाल मीना श्री अरविंद बालोत श्री प्रकाश ठाकुरिया श्री सुरेश कुमार
प्रतिवादी (ओं) के लिए	:	श्री जी.एस. राठौर, सामान्य सहायक- सह-एएजी, श्री अतुल शर्मा, पीपी के साथ श्री आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री जय नारायण शेर, पुलिस महानिरीक्षक, साथ में

श्रीमती नविता खोखर, पुलिस अधीक्षक,
व्यक्तिगत रूप से उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

आदेश

प्रकाशनीय

आरक्षित

घोषित

11/07/2024

02/08/2024

प्रस्तावना टिप्पणी:

1. वर्तमान रिट याचिका में राज्य और विशेष रूप से पुलिस प्राधिकारियों के संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है, जो उन व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने के संबंध में है, जिन्हें अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं या समूहों के हाथों अतिरिक्त कानूनी उत्पीड़न और/या हिंसा का खतरा है।

याचिकाकर्ताओं और बार के सदस्यों की प्रस्तुतियाँ:

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 बालिग दंपति हैं, जिन्होंने आपसी सहमति से 01.03.2024 को विवाह किया था। प्रस्तुत है कि याचिकाकर्ताओं को प्रतिवादी संख्या 6 से 10, जो याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्य हैं, से अपनी सुरक्षा को खतरा होने की आशंका है, और वे याचिकाकर्ताओं के विवाह को अपने सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए खतरा मानते हैं।

3. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 वे पुलिस अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध याचिकाकर्ताओं ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ताओं के जीवन को खतरे को उजागर करते हुए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय लागू करने की मांग करते हुए, पुलिस अधिकारियों के समक्ष 01.03.2024 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था। फिर भी, पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर उचित विचार नहीं किया गया।

4. इस न्यायालय को अक्सर ऐसे मामलों का निर्णय करने के लिए बुलाया जाता है, जिनमें अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए अतिरिक्त कानूनी खतरों की आशंका वाले व्यक्ति अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के लिए इस न्यायालय का

दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर होते हैं। यह न्यायालय नोट करता है कि प्रतिदिन, उपर्युक्त राहतों के लिए प्रार्थनाओं के साथ लगभग 15-20 याचिकाएँ इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती हैं, अक्सर पहली बार में और संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त उपायों के कार्यान्वयन के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष पहले कोई अभ्यावेदन दायर किए बिना। यह न्यायालय इस प्रकृति की याचिकाओं में उठाए जाने वाले जटिल और अक्सर विवादित तथ्यात्मक प्रश्नों पर निर्णय लेने में अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं की संस्थागत सीमाओं के प्रति सचेत है। उदाहरण के लिए, पुलिस सुरक्षा से संबंधित उन याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए, जो विवाहित/निकट संबंध में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती हैं, जिसमें वर्तमान रिट याचिका भी शामिल है, इस न्यायालय को सुरक्षा चाहने वाले संबंधित व्यक्तियों की आयु और राष्ट्रीयता सहित प्रश्नों पर तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा; पक्षों के बीच संबंधों की प्रकृति (विवाह, लिव-इन संबंध आदि); और संबंधित पक्षों, विशेषकर संबंधित महिलाओं, की ओर से विवाह/निकट संबंध के संबंध में स्वतंत्र सहमति का अस्तित्व। संविधान के अनुच्छेद 226 और बीएनएसएस 2023 की धारा 528 (सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के अनुरूप) के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति को देखते हुए, यह न्यायालय तथ्य-खोज के लिए तंत्रों को तैनात करने के माध्यम से तथ्य के ऐसे प्रश्नों पर निर्णय नहीं दे सकता है जो पहले उदाहरण के न्यायालयों के लिए उपलब्ध हैं और उनके द्वारा तैनात किए गए हैं। फिर भी, यह न्यायालय उन व्यक्तियों द्वारा पुलिस सुरक्षा से संबंधित याचिकाओं की एक बड़ी संख्या को दायर करने पर विचार करता है, जो अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त-कानूनी खतरों की आशंका करते हैं, जिनमें से अधिकांश याचिकाएं पहली बार इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाती हैं, एक अंतर्निहित प्रणालीगत अस्वस्थता का संकेत देती हैं, जिसके लिए संबंधित व्यक्तियों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

5. तदनुसार, दिनांक 03.07.2024 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने बार के सदस्यों को अगली सुनवाई की तिथि पर इस न्यायालय को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि ऐसे खतरों की आशंका वाले व्यक्तियों को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने हेतु मौजूदा तंत्र(ओं) और इन तंत्रों की कमियों के बारे में जानकारी मिल सके। बार के सदस्यों की बात सुनी गई और 11.07.2024 को इस रिट याचिका पर बहस पूरी हुई।

6. बार की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री सुखदेव सिंह सोलंकी, श्री चित्रांक शर्मा, श्री मोहरपाल द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियां दी गईं। मीणा , श्री अरविंद

बालोत , श्री प्रकाश ठाकुरिया और श्री सुरेश कुमार। विद्वान वकील ने कहा है कि जो व्यक्ति विवाहित हैं / करीबी रिश्ते में हैं, और जो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, वे अक्सर पुलिस अधिकारियों के समक्ष उस उद्देश्य के लिए संपर्क करने / प्रतिनिधित्व दायर करने में हिचकिचाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि संबंधित जोड़े डरते हैं कि उनके संवैधानिक अधिकार पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं होंगे, और यदि वे पुलिस अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो शायद आगे उनका उल्लंघन होगा। इसके अलावा, विद्वान वकील ने कहा है कि उन मामलों में भी जहां संबंधित जोड़ों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रतिनिधित्व दायर किया है, ऐसे प्रतिनिधित्वों पर विधिवत विचार नहीं किया जाता है और कानून के अनुसार निर्णय नहीं लिया जाता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित जोड़े यह सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हैं कि उनके संवैधानिक अधिकार उनके जीवन और स्वतंत्रता के लिए कथित अतिरिक्त-कानूनी खतरों से सुरक्षित हैं।

7. इस संबंध में, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि संबंधित जोड़े जो सुरक्षा से संबंधित उपायों की मांग करने के लिए पुलिस से संपर्क करते हैं, उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा में निम्नलिखित बाधाओं का सामना करना पड़ता है:

7.1 अधिकांश मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी संबंधित जोड़ों द्वारा दायर अभ्यावेदनों पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, और/या यह पता लगाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं नहीं करते हैं कि संबंधित जोड़ों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए या नहीं;

7.2 कई मामलों में, संबंधित पुलिस अधिकारी संविधान-विरुद्ध सामाजिक मानदंडों और पूर्वाग्रहों के आधार पर संबंधित जोड़ों को परेशान करते हैं। इसके अलावा, संबंधित पुलिस अधिकारी अक्सर उन सामाजिक तत्वों के साथ सांठगांठ कर लेते हैं जो जोड़े की स्वायत्तता को नष्ट करना चाहते हैं, जैसे कि उनके परिवार। ऐसी सांठगांठ अक्सर जोड़े, खासकर संबंधित महिला, को संबंधित पुलिस थाने में और/या संबंधित परिवार की हिरासत में जबरन हिरासत में ले लेती है, जो गैरकानूनी है और उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

7.3 अंतरजातीय या अंतरधार्मिक जोड़ों के मामले में ऐसा पुलिस उत्पीड़न और भी बढ़ जाता है, जिनके रिश्तों/विवाहों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिलती। इसलिए, संवैधानिक मूल्यों के विपरीत

सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध संबंधित जोड़ों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय, पुलिस ऐसे सामाजिक मानदंडों को वैध बनाने और उन्हें मज़बूत करने के लिए काम करती है।

8. तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं सहित, विवाहित/निकट संबंध में रहने वाले दम्पति, संविधान के भाग III, विशेषकर अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत अपने संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य हैं। अपने कथनों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ताओं ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **(2006) 5 एससीसी 475**; और शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (एआईआर **2018 एससी 1601**) में दिए गए निर्णयों का हवाला दिया है।

9. तदनुसार, पूर्वोक्त तर्कों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की गई कि इस रिट याचिका को उसमें की गई प्रार्थनाओं के अनुसार स्वीकार किया जाए। संक्षेप में, इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी-पुलिस अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु उचित उपाय करने के निर्देश देने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, बार के विद्वान सदस्यों, जिन्होंने 11.07.2024 को इस न्यायालय को संबोधित किया था, ने कुछ निर्देशों के लिए प्रार्थना की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन जोड़ों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाई जाए जो विवाहित हैं/निकट संबंध में हैं, और जो मौजूदा सामाजिक मानदंडों के उल्लंघन में अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं। जिन निर्देशों के लिए प्रार्थना की गई है उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

9.1 एक ऑनलाइन प्रणाली का निर्माण जिसके माध्यम से वे दम्पति, जिन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खतरा होने की आशंका है, पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं, जिस पर शीघ्रतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से निर्णय लिया जाएगा;

9.2 ऐसे अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने का उत्तरदायित्व पुलिस के अलावा अन्य प्राधिकारियों जैसे जिला मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या रजिस्ट्रार (न्यायिक) को सौंपा जाना;

9.3 शक्ति वाहिनी (सुप्रा) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुरूप आश्रय गृहों का निर्माण, जहां संबंधित दम्पतियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

प्रतिवादियों के प्रस्तुतियाँ:

10. इसके विपरीत, प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जीए-सह-ए.ए.जी श्री जी.एस. राठौर ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान कानून और कानूनी प्रक्रियाओं में उन जोड़ों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद हैं जो विवाहित हैं/निकट संबंध में हैं, जिसमें तत्काल रिट याचिका में याचिकाकर्ता भी शामिल हैं। इस संबंध में, इस न्यायालय के समक्ष इस आशय के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं कि 2023 और 2024 (मई 2024 तक) में संबंधित पुलिस अधिकारियों के समक्ष अपनी सुरक्षा को खतरा होने की आशंका वाले जोड़ों द्वारा दायर किए गए लगभग सभी अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया गया है और कानून के अनुसार उनका निपटारा किया गया है। इसके अलावा, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया है कि यदि ऐसे अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार नहीं किया जाता है और उनका निपटारा नहीं किया जाता है, तो उन्हें नामित पुलिस अधिकारियों, या राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत राज्य और जिला स्तर पर गठित 'पुलिस जवाबदेही समितियों' को सूचित किया जा सकता है।

11. इस रिट याचिका में दिनांक 03.07.2024 के आदेश के तहत, इस न्यायालय ने संबंधित राज्य प्राधिकारियों/पुलिस महानिदेशक कार्यालय, जयपुर को इस न्यायालय के समक्ष एक मानक संचालन प्रक्रिया (' एसओपी ') का मसौदा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जो पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर पुलिस प्राधिकारियों द्वारा विचार और निपटान को नियंत्रित करेगी। परिणामस्वरूप, एसओपी संख्या पृष्ठ 6 (40) पु0अ0/ म0अ0/ प्रेमी यु /पार्ट-2 /23/ इस न्यायालय के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

12. विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया है कि मसौदा एसओपी में विवाहित/निकट संबंध में रहने वाले जोड़ों द्वारा दायर पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के लिए किए गए अभ्यावेदनों के शीघ्र निपटान हेतु एक बहुस्तरीय और समयबद्ध व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत किया गया है कि मसौदा एसओपी उन जोड़ों के लिए संभावित कार्रवाई के तरीकों को भी निर्दिष्ट करता है जिनके अभ्यावेदनों पर संबंधित पुलिस अधिकारियों द्वारा विधिवत विचार या निर्णय नहीं लिया जाता है। इसके अलावा, प्रस्तुत किया गया है कि मसौदा एसओपी में कुछ व्हाट्सएप और हेल्पलाइन नंबरों का उल्लेख किया गया है, जिनके माध्यम से अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस करने वाले जोड़े पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा की जाए।

13. इसलिए, उपर्युक्त तर्कों पर भरोसा करते हुए, विद्वान एएजी ने तत्काल रिट याचिका और इस न्यायालय के समक्ष बार के विद्वान सदस्यों द्वारा की गई प्रार्थनाओं को खारिज करने की प्रार्थना की।

चर्चा और निष्कर्ष:

14. इस न्यायालय के समक्ष विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना और उन पर विचार किया, तत्काल रिट याचिका के अभिलेख का अवलोकन किया और बार में उद्धृत निर्णयों का अवलोकन किया।

15. इस न्यायालय के समक्ष अपने तर्कों के समर्थन में, याचिकाकर्ताओं और बार के सदस्यों के विद्वान अधिवक्ताओं ने मुख्यतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित संवैधानिक गारंटियों पर भरोसा किया है। उक्त संवैधानिक प्रावधान निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत हैं:

“अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समता

राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 21 - जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण

किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।”

16. लता सिंह (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वयस्क व्यक्तियों को वयस्क व्यक्तियों के साथ अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह करने की स्वायत्तता को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन घटनाओं की कड़ी निंदा की जहाँ कुछ सामाजिक तत्वों ने संबंधित जोड़े की व्यक्तिगत पसंद को कानून से परे दबाव डालकर विफल करने का प्रयास किया। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

“14. यह मामला एक चौंकाने वाली स्थिति को उजागर करता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता बालिग है और सभी प्रासंगिक समयों पर बालिग थी। इसलिए वह अपनी पसंद से किसी से भी विवाह करने या किसी के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। हिंदू विवाह अधिनियम या किसी अन्य कानून के तहत अंतर्जातीय विवाह पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि याचिकाकर्ता, उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों ने क्या अपराध किया है।

17. जाति व्यवस्था राष्ट्र के लिए एक अभिशाप है और इसे जितनी जल्दी नष्ट किया जाए उतना ही अच्छा है। वास्तव में, यह ऐसे समय में राष्ट्र को विभाजित कर रही है जब हमें राष्ट्र के सामने आने वाली चुनौतियों का एकजुट होकर सामना करने के लिए एकजुट होना होगा। इसलिए, अंतर्जातीय विवाह वास्तव में राष्ट्रहित में हैं क्योंकि इससे जाति व्यवस्था का नाश होगा। हालाँकि, देश के कई हिस्सों से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं कि अंतर्जातीय विवाह करने वाले युवक-युवतियों को हिंसा की धमकी दी जाती है, या उनके साथ हिंसा की जाती है। हमारी राय में, हिंसा, धमकी या उत्पीड़न के ऐसे कृत्य पूरी तरह से अवैध हैं और ऐसा करने वालों को कड़ी

सजा मिलनी चाहिए। यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम इतना कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते, हिंसा नहीं कर सकते या भड़का नहीं सकते और ऐसे अंतर्जातीय या अंतर्धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। ... “

17. संवैधानिक अधिकारों के ऐसे उल्लंघनों को रोकने और उन पर कार्रवाई करने में पुलिस की भूमिका और ज़िम्मेदारी के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह (सुप्रा) मामले में संबंधित दंपति की व्यक्तिगत पसंद की सुरक्षा में राज्य के एक अंग के रूप में पुलिस की संस्थागत भूमिका को मान्यता दी। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे भारत में पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए कि वयस्कता की आयु प्राप्त करने वाले और उसके बाद अंतरजातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले दंपतियों को कानून के बाहर उत्पीड़न और/या हिंसा से बचाया जाए। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

“15. हमारा मानना है कि किसी भी अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है और यह पूरा आपराधिक मामला याचिकाकर्ता के भाइयों के इशारे पर अदालती प्रक्रिया और प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग है, जो केवल इसलिए क्रोधित थे क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी जाति से बाहर विवाह किया था। हमें यह जानकर दुख हो रहा है कि याचिकाकर्ता के भाइयों के गैरकानूनी और अत्याचारी कृत्यों (जिनका विवरण ऊपर दिया गया है) के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय, पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है।

17. ... इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई बालिग लड़का या लड़की किसी बालिग महिला या पुरुष के साथ अंतरजातीय या अंतरधार्मिक विवाह करता है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें धमकी दी जाएगी या हिंसा का कार्य किया जाएगा, और जो कोई भी ऐसी धमकी देता है या परेशान करता है या स्वयं या उसके उकसावे पर हिंसा का कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाएगी और कानून द्वारा प्रदान की गई कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

19. इन परिस्थितियों में, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। सत्र परीक्षण संख्या 1201/2001, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संगीता गुप्ता, जो कि थाना सरोजिनी नगर, लखनऊ में दर्ज एफआईआर संख्या 336/2000 से उत्पन्न हुई और फास्ट ट्रैक कोर्ट V, लखनऊ में लंबित है, की कार्यवाही रद्द की जाती है। अभियुक्तों के विरुद्ध वारंट भी रद्द किए जाते हैं। सभी संबंधित स्थानों की पुलिस यह सुनिश्चित करे कि न तो

याचिकाकर्ता, न ही उसके पति, न ही याचिकाकर्ता के पति के किसी रिश्तेदार को परेशान किया जाए या धमकाया जाए और न ही उनके विरुद्ध कोई हिंसा की जाए। यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

18. शक्ति वाहिनी (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए 'सम्मान' संबंधी अपराधों के संदर्भ में, लता सिंह (सुप्रा) मामले में दिए गए निर्णय में दिए गए अपने तर्कों और निर्देशों को दोहराया। शक्ति वाहिनी (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति के जीवनसाथी या जीवनसाथी का चुनाव गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता का एक अंतर्निहित पहलू है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक रूप से संरक्षित किया गया है। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार पुनः प्रस्तुत हैं:

"42. ... ऑनर किलिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पसंद की आज्ञादी और पसंद के बारे में व्यक्ति की अपनी धारणा को खत्म कर देती है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जब दो वयस्क सहमति से एक-दूसरे को जीवनसाथी चुनते हैं, तो यह उनकी पसंद का प्रकटीकरण होता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। ऐसे अधिकार को संवैधानिक कानून का समर्थन प्राप्त है और एक बार मान्यता मिल जाने के बाद, उक्त अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए और इसे वर्ग सम्मान या समूह सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुकना चाहिए, जिसकी कल्पना किसी ऐसी धारणा पर की जाती है जिसकी दूर-दूर तक कोई वैधता नहीं है।

44. किसी व्यक्ति की पसंद गरिमा का अभिन्न अंग है, क्योंकि जहाँ पसंद का क्षरण होता है, वहाँ गरिमा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह सच है कि यह संवैधानिक सीमा के सिद्धांत से बंधा है, लेकिन ऐसी सीमा के अभाव में, किसी को भी, हमारा मतलब है, किसी को भी उक्त पसंद के फलित होने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी की अपनी पसंद व्यक्त करने के अधिकार में बाधा डाली जाती है, तो गरिमा की पवित्र पूर्णता के बारे में सोचना बेहद मुश्किल होगा। जब दो वयस्क अपनी इच्छा से विवाह करते हैं, तो वे अपना रास्ता चुनते हैं; वे अपने रिश्ते को परिपूर्ण करते हैं; उन्हें लगता है कि यही उनका लक्ष्य है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। और यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि उन्हें अधिकार है और उक्त अधिकार का कोई भी उल्लंघन संवैधानिक उल्लंघन है। ..."

19. इसके अलावा, शक्ति वाहिनी (सुप्रा) मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सामाजिक मानदंडों की अवहेलना करते हुए अपने साथी/जीवनसाथी चुनने के लिए अपनी व्यक्तिगत पसंद का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध, 'सम्मान' के नाम पर, विधि-बाह्य उत्पीड़न या हिंसा करने की अवैध लेकिन सामाजिक रूप से वैध प्रथा की कड़ी निंदा की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि

इस तरह का विधि-बाह्य उत्पीड़न या हिंसा विधि के शासन का अपमान है और परिवार तथा समाज में महिलाओं की भूमिका और स्थिति के बारे में सामाजिक पूर्वाग्रहों पर आधारित है। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

“1. ...जो प्रश्न विचारणीय है वह यह है कि क्या परिवार या कुल के बुजुर्गों को कभी भी किसी जुनून से प्रेरित होकर फैसला सुनाने और उन युवाओं का जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने अपने बुजुर्गों की इच्छा के विरुद्ध या कुल की प्रचलित प्रथा के विपरीत विवाह करने का निर्णय लिया है। इसका उत्तर निश्चित रूप से “नहीं” होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता का सागर और गरिमा की गहरी भावना इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करती क्योंकि व्यवहार का स्वरूप किसी असंवैधानिक धारणा पर आधारित होता है। ...

4. यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे माहौल में एक महिला का अस्तित्व पूरी तरह से परिवार, समुदाय और परिवेश की प्रतिष्ठा के बारे में पुरुषों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी-कभी, यह विरासत में मिले स्थानीय लोकाचार पर केंद्रित होता है, जो तार्किक रूप से समझ से परे होता है। सामुदायिक मानदंडों से परे अपनी पसंद के अनुसार जीवनसाथी चुनने में किसी महिला या पुरुष की कार्यवाई को अपमानजनक माना जाता है, जो अंततः सामुदायिक नुस्खे के क्रूर हाथों में निर्दोष रूप से मृत्यु को आमंत्रित करता है। एक महिला की प्रतिष्ठा उसके आचरण के अनुसार आंकी जाती है, और जिस परिवार से लड़की या महिला संबंधित है, उस पर दबाव डाला जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिवार के सदस्य, कुछ अवसरों पर, किए गए व्यवहार के मूक दर्शक बन जाते हैं या कभी-कभी दृढ़ व्यवहार या पारिवारिक गौरव की प्राप्ति की अवांछित भावना के कारण समूह का हिस्सा बनकर सक्रिय भागीदार बन जाते हैं।

5. जिस सम्मान की अवधारणा से हम चिंतित हैं, उसके कई पहलू हैं। कभी-कभी, कोई युवक ऑनर किलिंग का शिकार हो सकता है या लड़की के परिवार वालों के हाथों हिंसक व्यवहार का शिकार हो सकता है, जब वह प्रेम में पड़ जाता है या विवाह कर लेता है। यह समूह एक पितृसत्तात्मक सम्राट की तरह व्यवहार करता है जो अपनी पत्नियों, बहनों और बेटियों के साथ अधीनस्थ, यहाँ तक कि दास या आत्मत्यागी व्यवहार करता है, जो शारीरिक रूप से गतिमान व्यक्ति हैं, जिनकी कोई व्यक्तिगत स्वायत्तता, इच्छा और पहचान नहीं है। समुदाय के पुरुष सदस्यों और एक प्रकार की आत्म-जागरूकता की भावना द्वारा स्थिति की अवधारणा को बल मिलता है। पुरुष प्रधानता, प्रत्यक्ष सम्मान का एकमात्र नियामक कारक बन जाती है।

7. ... इस समूह द्वारा संवैधानिक प्रावधानों का बहुत कम सम्मान किया जाता है और मानवीय गरिमा को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। अनुच्छेद 21, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा और बुनियादी मानवाधिकारों व प्रतिष्ठा की समानता की रक्षा करता है, को इन पंचायतों या उन समूहों द्वारा, जो ज़रा भी

अंतरात्मा की पीड़ा के बिना, ऑनर किलिंग का समर्थन करते हैं, बेशर्मी से नकार दिया गया है। ...

39. ... किसी बेटी, भाई, बहन या बेटे के मानवाधिकार परिवार, कुल या सामूहिक के तथाकथित या तथाकथित सम्मान के आगे गिरवी नहीं रखे जा सकते। ऑनर किलिंग का कृत्य कानून के शासन को एक भयावह संकट में डाल देता है।

41. हमने ऊपर जो कहा है, उसे स्पष्ट करने के लिए, वह यह है कि एक बार दो वयस्क व्यक्ति विवाह बंधन में बंधने के लिए सहमत हो जाने पर परिवार या समुदाय या कुल की सहमति आवश्यक नहीं है। उनकी सहमति को पवित्रतापूर्वक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि किसी दंडात्मक कानून के कारण कोई अपराध करता है, तो उसका निर्णय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए जिसे आपराधिकता का निर्धारण कहा जाता है। यह न्याय प्रदान करने के लिए अनौपचारिक संस्थाओं के लिए कोई स्थान नहीं मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 'कानून के शासन' द्वारा शासित राजनीति केवल ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए स्थापित औपचारिक संस्थाओं द्वारा अधिकारों के निर्धारण और उनके उल्लंघन को ही स्वीकार करती है। यह निरंतर ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक अवधारणा के रूप में कानून का शासन समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए है। यह मानवाधिकारों का सम्मान करता है। इसलिए, खाप पंचायत या किसी भी नाम की कोई भी पंचायत उक्त अधिकार के प्रयोग में बाधा नहीं डाल सकती है।

44. ... वर्ग या कुल के उच्च सम्मान के नाम पर बहुसंख्यक उनकी उपस्थिति का आह्वान या उनकी उपस्थिति को बलपूर्वक लागू नहीं कर सकते, मानो वे किसी अवर्णनीय युग के सम्राट हों, जिनके पास कोई भी दंड देने और उसके निष्पादन को अपनी इच्छानुसार निर्धारित करने की शक्ति, अधिकार और अंतिम निर्णय है, संभवतः इस धारणा को पोषित करते हुए कि वे स्वयं एक कानून हैं या वे सीज़र या, इस मामले में, लुई चौदहवें के पूर्वज हैं। इस देश का संविधान और कानून ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करते हैं और वास्तव में, यह पूरी गतिविधि अवैध है और आपराधिक कानून के तहत अपराध के रूप में दंडनीय है।”

20. तदनुसार, 'सम्मान' के आधार पर अपराधों की व्यापक सामाजिक प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति वाहिनी (सुप्रा) के निर्णय में कुछ निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक निर्देश जारी किए। इस रिट याचिका और इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मुद्दे के प्रयोजनों के लिए, यह महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ (1) उपर्युक्त 'सम्मान' के आधार पर अपराधों को रोकने; और (2) संबंधित जोड़े को अन्य सामाजिक कर्ताओं या समूहों द्वारा अतिरिक्त-कानूनी उत्पीड़न और हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को अन्य बातों के साथ-साथ उन संबंधित जोड़ों के लिए 'सुरक्षित घर' स्थापित करने का निर्देश दिया,

जिन्हें उपर्युक्त व्यक्तिगत पसंद के कारण अतिरिक्त-कानूनी उत्पीड़न या जबरदस्ती की धमकी दी गई थी। पुलिस सुरक्षा और सुरक्षित घरों की स्थापना से संबंधित निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत हैं:

"48. सम्मान के नाम पर होने वाले अपराधों की क्रूरता और समाज पर इस प्रकार के अपराधों के विनाशकारी प्रभाव को देखते हुए, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों के लिए निर्देश जारी करना वांछनीय है। हम ऐसा सोचने के लिए तैयार हैं क्योंकि राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसा वातावरण बनाए जहाँ नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का आनंद ले सकें। ...

53. श्री राजू रामचंद्रन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जिन्हें श्री गौरव अग्रवाल सहायता प्रदान कर रहे हैं, ने दिशानिर्देश जारी करने के लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं। भारत संघ ने भी कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर कानून बनने तक विचार किया जाना चाहिए। सम्मान-अपराध के कष्टदायक प्रभाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए, हमारा मानना है कि निवारक, उपचारात्मक और दंडात्मक उपाय किए जाने चाहिए और तदनुसार, हम संबंधित राज्यों की कार्यपालिका और पुलिस प्रशासन को उक्त उद्देश्यों के लिए एक सुदृढ़ तंत्र विकसित करने हेतु और उपाय जोड़ने की स्वतंत्रता के साथ व्यापक रूपरेखा और तौर-तरीके बताते हैं। ...

II. उपचारात्मक उपायः

...

(ग) इसके अतिरिक्त, जोड़े/परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो उनकी सुरक्षा और खतरे की धारणा को ध्यान में रखते हुए उन्हें उसी जिले या अन्यत्र एक सुरक्षित घर में ले जाया जाना चाहिए। राज्य सरकार उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक सुरक्षित घर स्थापित करने पर विचार कर सकती है। ऐसे सुरक्षित घरों में (i) युवा कुंवारे-कुंवारी जोड़ों को रखा जा सकता है जिनके रिश्ते का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जा रहा है और (ii) युवा विवाहित जोड़ों (अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक या किसी अन्य विवाह का उनके परिवारों/स्थानीय समुदाय/खापों द्वारा विरोध किया जा रहा है)। ऐसे सुरक्षित घरों को क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की देखरेख में रखा जा सकता है।

(घ) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक को ऐसे दंपति/परिवार को दी गई धमकी से संबंधित शिकायत को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ निपटाना चाहिए। सबसे पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या कुंवारे-कुंवारी सक्षम वयस्क हैं। इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें विवाह संपन्न कराने और/या पुलिस सुरक्षा में विधिवत पंजीकरण कराने के लिए, यदि वे चाहें, तो आवश्यक सहायता प्रदान की जा सकती है। विवाह के बाद, यदि दंपति चाहें, तो उन्हें नाममात्र शुल्क के भुगतान पर सुरक्षित घर में एक महीने की अवधि के लिए आवास प्रदान किया जा सकता है,

जिसे मामले-दर-मामला उनके खतरे के आकलन के आधार पर मासिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक नहीं।...”

21. लता सिंह (सुप्रा) और शक्ति वाहिनी (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तर्क और निर्देशों के आलोक में, यह न्यायालय पुष्टि करता है कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटी उन वयस्क व्यक्तियों के लिए बड़ी हुई पुलिस सुरक्षा के दावे को मजबूत करती है जो अपने साथी/जीवनसाथी चुनने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार अन्य सामाजिक अभिनेताओं या समूहों से अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कानूनी खतरों की आशंका करते हैं। ऐसी स्थितियों में, न केवल संबंधित जोड़ों के जीवन और स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को नकार दिया जाता है, बल्कि कानून के शासन की संवैधानिक इमारत को भी खतरा होता है। इसके अलावा, संबंधित जोड़ों द्वारा उत्पीड़न और हिंसा के अतिरिक्त कानूनी रूप जो आशंका करते हैं, वे पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों में निहित हैं

22. इस संबंध में, यह न्यायालय राज्य और उसके निकायों के संवैधानिक कर्तव्य को स्वीकार करता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वयस्कता प्राप्त करने के बाद संबंधित व्यक्तियों की अपने जीवनसाथी/साथी चुनने की स्वायत्तता का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन करने के लिए उपयुक्त कानून और नीतियाँ बनाई और लागू की जाएँ। यह निष्कर्ष संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को अनुच्छेद 12 और 13 के साथ पढ़ने पर अनिवार्य रूप से निकलता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह (सुप्रा) और शक्ति वाहिनी (सुप्रा) में अपने निर्णयों में इसे बरकरार रखा है।

23. उपर्युक्त संवैधानिक कर्तव्य का एक महत्वपूर्ण तत्व पुलिस अधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है कि वे संबंधित दम्पतियों को उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दम्पति विधि-बाह्य उत्पीड़न या हिंसा की सीमाओं से मुक्त होकर अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता का प्रयोग कर सकें। इस संवैधानिक दायित्व को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लता सिंह (सुप्रा) और शक्ति वाहिनी (सुप्रा) के मामलों में मान्यता दी है। इसके अतिरिक्त, यह भारतीय संविधान की धारा 168 और 169 में भी वैधानिक रूप से प्रतिबिम्बित है। नागरिक सुरक्षा संहिता , 2023 (दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 149 और 150 के अनुरूप), जो संज्ञेय अपराधों की रोकथाम से संबंधित पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का वर्णन करती है; और राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29, जो पुलिस अधिकारियों के विभिन्न कर्तव्यों को निर्दिष्ट करती है। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023

धारा **168** - संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस

प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के होने को रोकने के प्रयोजन के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, और अपनी पूरी क्षमता से उसे रोकेगा।

धारा **169** - संज्ञेय अपराध करने की योजना की सूचना

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की योजना की सूचना प्राप्त होने पर, ऐसी सूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, तथा किसी अन्य अधिकारी को, जिसका कर्तव्य ऐसे किसी अपराध के किए जाने को रोकना या उसका संज्ञान लेना है, संसूचित करनी होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

धारा **149** - संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए पुलिस

प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है और अपनी पूरी क्षमता से ऐसा करेगा।

धारा **150** - संज्ञेय अपराध करने की योजना की सूचना

प्रत्येक पुलिस अधिकारी को, किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की योजना की सूचना प्राप्त होने पर, ऐसी सूचना उस पुलिस अधिकारी को, जिसके वह अधीनस्थ है, तथा किसी अन्य अधिकारी को, जिसका कर्तव्य ऐसे किसी अपराध के किए जाने को रोकना या उसका संज्ञान लेना है, संसूचित करनी होगी।

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007

धारा **29** - पुलिस अधिकारियों के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ

(1) पुलिस अधिकारी के कार्य, कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित होंगी:

(क) कानून को लागू करना , तथा लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, अधिकार, सम्मान और मानवाधिकारों की रक्षा करना;

(ख) अपराध और सार्वजनिक उपद्रव को रोकने के लिए ;

(ग) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना ;

(घ) आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना , आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और नियंत्रित करना, तथा सार्वजनिक शांति भंग होने से रोकना;

(ङ) सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ;

(च) अपराधों का पता लगाना और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना;

(छ) ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए वह विधिक रूप से प्राधिकृत है और जिनकी गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं;

(ज) प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं से उत्पन्न परिस्थितियों में लोगों की सहायता करना, तथा राहत उपायों में अन्य एजेंसियों की सहायता करना ;

(झ) लोगों और वाहनों की व्यवस्थित आवाजाही को सुगम बनाना तथा यातायात को नियंत्रित और विनियमित करना;

(ञ) सार्वजनिक शांति और अपराध को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित खुफिया जानकारी इकट्ठा करना ;

(ट) सार्वजनिक प्राधिकारियों को उनके कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में सुरक्षा प्रदान करना; और

(ठ) ऐसे कर्तव्यों का पालन करना तथा ऐसे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो उसे विधि द्वारा या किसी विधि के अधीन ऐसे निर्देश जारी करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा सौंपे जाएं।

(2) राज्य सरकार, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त प्राधिकारी, पुलिस अधिकारियों को ऐसे अन्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां सौंप सकेगा, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

24. एक अलग नज़रिए से, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संवैधानिक जिम्मेदारी अनिवार्य रूप से पुलिस की संस्थागत शक्तियों से प्रवाहित होती है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाली प्राथमिक संस्थाओं में से एक है, जहाँ राज्य का वैध प्रकार के दबाव पर एकाधिकार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। संविधान की सर्वोच्चता पर निर्मित एक संवैधानिक ढाँचे के भीतर, ऐसी संस्थागत शक्तियों का प्रयोग केवल संवैधानिक दृष्टिकोण और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए ही किया जाना चाहिए; और वह भी केवल संवैधानिक प्रावधानों और संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरे उतरने वाले कानूनों के अनुसार। इसलिए, पुलिस अधिकारियों की यह संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वे उन संबंधित जोड़ों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करें जिनकी स्वायत्तता सामाजिक कर्ताओं या समूहों द्वारा बाधित होने की आशंका है, जो प्रमुख सामाजिक मानदंडों को मज़बूत करने के लिए कानून के बाहर उत्पीड़न या धमकियाँ देते हैं। तदनुसार, यदि पुलिस अधिकारी पूर्वोक्त रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो उपयुक्त संस्थागत तंत्र मौजूद होना चाहिए जो पीड़ित व्यक्तियों के लिए सुलभ हो, और जो यह सुनिश्चित करे कि संबंधित पुलिस अधिकारियों को परिणामी संवैधानिक और कानूनी उल्लंघनों की घटना को रोकने/सांठगांठ करने में उनकी विफलता के लिए जवाबदेह ठहराया जाए।

25. पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संस्थागत तंत्र के महत्व को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य **(2006) 8 एससीसी 1** के फैसले में रेखांकित किया था। इस फैसले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश के भीतर पुलिस अधिकारियों पर मौजूदा राजनीतिक प्रभाव से संबंधित याचिकाकर्ताओं की दलीलें दर्ज कीं, जिसके परिणामस्वरूप राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों को कानून का उल्लंघन करने का लाभ मिला। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचार में, संवैधानिक मानदंडों और मूल्यों के अनुसार कार्य करने की पुलिस की संवैधानिक जिम्मेदारी को देखते हुए, पुलिस पर इस तरह के बाहरी प्रभाव संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य थे। फैसले के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत हैं:

“10. याचिका में कहा गया है कि नागरिकों के मौलिक और मानवाधिकारों का उल्लंघन आम तौर पर कानूनों के गैर-प्रवर्तन और भेदभावपूर्ण अनुप्रयोग की प्रकृति का होता है, जिससे प्रभावशाली लोगों को कानूनों के ज़बरदस्त उल्लंघन के लिए भी जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है और किसी भी स्थिति में, अनधिकृत हिरासत, यातना, उत्पीड़न, साक्ष्य गढ़ने, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन आदि के रूप में नागरिकों के अधिकारों के प्रत्यक्ष उल्लंघन के लिए उन्हें न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता है। याचिका में पुलिस की निष्क्रियता के कुछ ज्वलंत उदाहरण दिए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, पुलिस के कामकाज में वर्तमान विकृतियों और विचलन की जड़ें 1861 के पुलिस अधिनियम में हैं, पुलिस की संरचना और संगठन मूल रूप से इतने वर्षों से अपरिवर्तित रहे हैं।

11. याचिका में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए कारण बताए गए हैं कि पुलिस की कार्यप्रणाली ने इतनी निराशा और असंतोष क्यों पैदा किया है। इसमें विभिन्न समितियों की सिफारिशें भी शामिल हैं जिन्हें कभी लागू नहीं किया गया। चूंकि पुलिस के दुरुपयोग और दुर्यवहार ने इसे बेईमान आकाओं के हाथों में एक मात्र उपकरण बना दिया है और इस प्रक्रिया में, इसने लोगों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया है, इसलिए यह तर्क दिया गया है कि पुलिस के कार्यक्षेत्र और कार्यों को पुनः परिभाषित करने, देश के कानून के प्रति उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की प्रमुख सिफारिशों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है। याचिका में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 1979 में प्रकाशित एक शोध पत्र 'पुलिस का राजनीतिक और प्रशासनिक हेरफेर' का हवाला दिया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि राजनीतिक कार्यपालिका और उसके प्रमुख सलाहकारों का पुलिस पर अत्यधिक नियंत्रण पुलिस को कानून की प्रक्रिया को विफल करने, अधिनायकवाद को बढ़ावा देने और लोकतंत्र की नींव हिलाने का एक उपकरण बनाने का अंतर्निहित खतरा पैदा करता है।

12. पुलिस की प्रतिबद्धता, समर्पण और जवाबदेही केवल कानून के शासन के प्रति होनी चाहिए। पर्यवेक्षण और नियंत्रण ऐसा होना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो कि

पुलिस किसी भी अपराध की जाँच या निवारक उपाय करते समय, किसी भी व्यक्ति की स्थिति और पद की परवाह किए बिना, जनता की सेवा करे। उसका दृष्टिकोण सेवा-उन्मुख होना चाहिए, उसकी भूमिका इस प्रकार परिभाषित होनी चाहिए कि उचित मामलों में, जहाँ पुलिस की चूक और चूक के कारण कानून का शासन प्रभावित होता है, दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जाए।

26. (i) समस्या की गंभीरता; (ii) कानून के शासन के संरक्षण और सुदृढीकरण की तत्काल आवश्यकता; (iii) पिछले दस वर्षों से इस याचिका के लंबित होने; (iv) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभिन्न आयोगों और समितियों ने देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए इसी तरह की सिफारिशों की हैं; और (v) पुलिस सुधार कब लागू होंगे, इस बारे में पूर्ण अनिश्चितता, हम समझते हैं कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता है, और तत्काल अनुपालन के लिए उचित निर्देश जारी करने का समय आ गया है ताकि केंद्र सरकार द्वारा एक नया मॉडल पुलिस अधिनियम तैयार किए जाने और/या राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित कानून पारित किए जाने तक ये निर्देश प्रभावी रहें। यह भी ध्यान देने योग्य है कि देश में आपराधिक न्याय प्रणाली की गुणवत्ता काफी हद तक पुलिस बल के कामकाज पर निर्भर करती है। इसलिए, व्यापक जनहित को ध्यान में रखते हुए, अपेक्षित निर्देश जारी करना नितांत आवश्यक है। लगभग दस साल पहले, विनीत नारायण बनाम भारत संघ¹ में, इस न्यायालय ने राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षित तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता पर ध्यान दिया और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकारों के साथ पुलिस सुधारों के मामले को आगे बढ़ाए और न केवल राज्य पुलिस प्रमुख, बल्कि पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के सभी पुलिस अधिकारियों के चयन/नियुक्ति, कार्यकाल, स्थानांतरण और पोस्टिंग के लिए एक तंत्र की स्थापना सुनिश्चित करे। न्यायालय ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ राज्यों में पुलिस अधीक्षक का कार्यकाल कुछ महीनों का होता है और मनमाने कारणों से स्थानांतरण किए जाते हैं, जिसका न केवल पुलिस बल पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ता है, बल्कि यह परिकल्पित संवैधानिक तंत्र के भी विपरीत है। यह देखा गया कि पुलिस बल का मनोबल गिराने के अलावा, इससे कर्मियों का राजनीतिकरण भी होता है और इसलिए, यह आवश्यक है कि केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र उपाय किए जाएं।

29. केंद्र सरकार द्वारा एक आदर्श पुलिस अधिनियम तैयार करना और राज्य सरकारों द्वारा नए पुलिस अधिनियमों को लागू करना, जिसमें राज्य सुरक्षा आयोग के गठन का प्रावधान हो, ऐसी बातें हैं जिनकी हम वर्तमान में केवल आशा ही कर सकते हैं। इसी प्रकार, हम केवल यह आशा व्यक्त कर सकते हैं कि सभी राज्य सरकारें इस अवसर पर आगे आएँगी और एक नया पुलिस अधिनियम लागू करेंगी जो पुलिस को किसी भी प्रकार के दबाव से पूरी तरह मुक्त करेगा, जिससे संविधान के तहत नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय लागू होगा, जिसमें

सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा और किसी के प्रति पक्षपात नहीं किया जाएगा, जिससे एक कुशल और बेहतर आपराधिक न्याय प्रणाली सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। इस मामले को केवल इस आशा की अभिव्यक्ति के साथ छोड़ देना और आगे के घटनाक्रमों की प्रतीक्षा करना संभव या उचित नहीं है। राज्य सरकारों द्वारा नए कानून के लागू होने तक लागू रहने वाले दिशानिर्देश निर्धारित करना आवश्यक है।”

26. तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए कि देश भर के पुलिस अधिकारियों को बाहरी प्रभावों से बचाया जाए और उन्हें लागू संवैधानिक एवं वैधानिक मानदंडों के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। इन निर्देशों में से, राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' का गठन इस रिट याचिका के निर्णय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। निर्णय के प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैं:

“30. संविधान के अनुच्छेद 32 के साथ अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को ऐसे निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, जो किसी भी मामले या वाद में पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक हो सकते हैं। अनुच्छेद 144 के तहत सभी प्राधिकारियों को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। विनीत मामले में निर्णय नारायण मामले में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया गया है, जहां अनुपालन हेतु दिशानिर्देश और निर्देश कानून के अभाव में जारी किए गए थे और लागू किए गए कानून थे। जब तक विधायिकाएं उचित निर्णय नहीं ले लेतीं, तब तक

31. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सहायता से, हमने विभिन्न रिपोर्टों का अवलोकन किया है। उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अपने संवैधानिक कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन करते हुए, हम केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त विधानों के निर्माण तक अनुपालन हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

....

पुलिस शिकायत प्राधिकरण:

(6) जिला स्तर पर एक पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा जो पुलिस उपाधीक्षक और उसके रैंक तक के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा। इसी प्रकार, राज्य स्तर पर एक और पुलिस शिकायत प्राधिकरण होगा जो पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच करेगा। जिला स्तरीय प्राधिकरण का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश कर सकते हैं जबकि राज्य स्तरीय प्राधिकरण का नेतृत्व उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर सकते हैं। राज्य स्तरीय शिकायत प्राधिकरण के प्रमुख का चयन राज्य सरकार द्वारा मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से किया जाएगा; जिला स्तरीय शिकायत प्राधिकरण के प्रमुख का चयन मुख्य

न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा प्रस्तावित नामों के पैनल में से भी किया जा सकता है। विभिन्न राज्यों/जिलों में शिकायतों की मात्रा के आधार पर इन प्राधिकरणों को तीन से पांच सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है, और उनका चयन राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग/ लोक आयुक्त /राज्य लोक सेवा आयोग। पैनल में सेवानिवृत्त सिविल सेवक, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य विभाग के अधिकारी या नागरिक समाज के सदस्य शामिल हो सकते हैं। वे प्राधिकरण के लिए पूर्णकालिक काम करेंगे और उन्हें उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। क्षेत्रीय पृष्ठताछ करने के लिए प्राधिकरण को नियमित कर्मचारियों की सेवाओं की भी आवश्यकता हो सकती है। इस प्रयोजन के लिए, वे सीआईडी, खुफिया, सतर्कता या किसी अन्य संगठन के सेवानिवृत्त जांचकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। राज्य स्तरीय शिकायत प्राधिकरण केवल पुलिसकर्मियों द्वारा गंभीर कदाचार के आरोपों का संज्ञान लेगा, जिसमें पुलिस हिरासत में मृत्यु, गंभीर चोट या बलात्कार की घटनाएं शामिल होंगी। जिला स्तरीय शिकायत प्राधिकरण, उपरोक्त मामलों के अलावा, जबरन वसूली, भूमि/मकान हड़पने या अधिकार के गंभीर दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी घटना के आरोपों की भी जांच कर सकता है। किसी दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई, विभागीय या आपराधिक, के लिए जिला और राज्य दोनों स्तरों पर शिकायत प्राधिकरण की सिफारिशें संबंधित प्राधिकरण के लिए बाध्यकारी होंगी।

...

उपर्युक्त निर्देशों का पालन केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा, जैसा भी मामला हो, 31 दिसंबर, 2006 को या उससे पहले किया जाना चाहिए ताकि पूर्वोक्त निकाय नए वर्ष की शुरुआत में कार्यरत हो सकें। भारत सरकार के कैबिनेट सचिव और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 3 जनवरी, 2007 तक अनुपालन के हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

27. यह न्यायालय प्रकाश सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में राजस्थान राज्य की विफलता को दर्ज करता है। राजस्थान के संदर्भ में 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के गठन के संबंध में, इस न्यायालय का ध्यान राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62 से 69 की ओर आकर्षित किया गया, जो राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस जवाबदेही समितियों' के गठन और कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं को प्रतिपादित करती हैं। संबंधित वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"धारा 62 - पुलिस जवाबदेही

(1) राज्य सरकार यथाशीघ्र प्रत्येक जिले या जिलों के समूह के लिए एक राज्य पुलिस जवाबदेही समिति (जिसे आगे "राज्य समिति" कहा जाएगा) और जिला जवाबदेही समिति (जिसे आगे "जिला समिति" कहा जाएगा) स्थापित कर सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन स्थापित समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसा मानदेय और जेबखर्च दिया जा सकेगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

धारा 63 - राज्य समिति

(1) राज्य समिति में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पांच सदस्य नामित किए जाएंगे:

(क) सार्वजनिक व्यवहार में अनुभव रखने वाले तथा मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का विश्वसनीय रिकार्ड रखने वाले चार प्रतिष्ठित व्यक्ति स्वतंत्र सदस्य के रूप में: बशर्ते कि एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्गों से होगा तथा एक महिला होगी;

(ख) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर का एक अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा;

(ग) सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से एक को राज्य समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(2) राज्य समिति को ऐसी सचिवीय सहायता प्रदान की जा सकेगी, जिसे सरकार समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित करे।

धारा 64 - राज्य समिति के कार्य

राज्य समिति के कार्य निम्नानुसार होंगे:

(क) पर्यवेक्षी रैंक के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध "गंभीर कदाचार" के आरोपों की जांच करना, या तो स्वप्रेरणा से या पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति या जिला समिति से प्राप्त शिकायत पर;

(ख) ऐसे अन्य कार्य करना जिन्हें सरकार समय-समय पर निर्दिष्ट करे;

(ग) जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य सरकार को उसके द्वारा शुरू किए गए किसी मामले पर सिफारिशें करना। स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजन के लिए "गंभीर कदाचार" का अर्थ होगा:

(I) किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किया गया कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसके परिणामस्वरूप या जिसकी मात्रा निम्न हो:

(i) गंभीर चोट;

(ii) अवैध हिरासत; या

(iii) कोई अन्य अपराध जिसके लिए कानून में निर्धारित अधिकतम सजा दस वर्ष या उससे अधिक है।

(II) पुलिस अधिकारी द्वारा जबरन वसूली।

धारा 65 - राज्य समिति की शक्तियाँ

राज्य समिति को, इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5, 1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय न्यायालय को प्राप्त होती हैं, अर्थात्:

(क) किसी व्यक्ति को उपस्थित कराना तथा शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना ; और

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना, तथा समिति के समक्ष कार्यवाही भारतीय दंड संहिता, 1860 (1869 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 45) की धारा 193, 196 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी।

धारा **66** - जिला समिति

(1) जिला समिति में राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पांच सदस्य नामित किये जायेंगे :

(क) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जिन्हें सार्वजनिक व्यवहार का अनुभव हो तथा जिनका मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का विश्वसनीय रिकार्ड हो, स्वतंत्र सदस्य के रूप में होंगे: बशर्ते कि एक स्वतंत्र सदस्य समाज के कमजोर वर्गों से होगा तथा एक महिला होगी।

(ख) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर का एक अधिकारी इसका सदस्य सचिव होगा;

(ग) सरकार स्वतंत्र सदस्यों में से एक को जिला समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

धारा **67** - जिला समिति के कार्य

जिला समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

(क) अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच करना, चाहे वह स्वप्रेरणा से हो या शिकायत पर, तथा संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी को अपनी सिफारिशें भेजना: परंतु अनुशासनात्मक प्राधिकारी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर तीन महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेगा तथा निर्णय की एक प्रति समिति की जानकारी के लिए भी भेजेगा;

(ख) अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की निगरानी करना ;

(ग) पर्यवेक्षी रैंक के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों तथा ऐसे अन्य मामलों को राज्य समिति को संदर्भित करना, जिन्हें वह उचित समझे ।

धारा **68** - समितियों के स्वतंत्र सदस्यों का कार्यकाल

(1) राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष का होगा और किसी स्वतंत्र सदस्य को उसी समिति में दूसरे कार्यकाल के लिए नामित नहीं किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, राज्य समिति या जिला समिति के किसी स्वतंत्र सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह धारा 69 में विनिर्दिष्ट कोई निरर्हता प्राप्त कर लेता है, या यदि वह स्वतंत्र सदस्य के रूप में उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है।

धारा **69** - स्वतंत्र सदस्य के रूप में नामांकन के लिए अयोग्यता

कोई व्यक्ति राज्य समिति या जिला समिति के स्वतंत्र सदस्य के रूप में मनोनीत होने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह

(क) भारत का नागरिक नहीं है;

- (ख) जिसे किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो, या जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध के आरोप विरचित किए गए हों ;
- (ग) किसी सार्वजनिक सेवा से बर्खास्त, हटाया गया या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो ;
- (घ) न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो ;
- (ङ) विकृत चित्त का है ; या
- (च) संसद या राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय का सदस्य है या रहा है; या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध संगठन का पदाधिकारी है या रहा है; या किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध संगठन का सदस्य है या रहा है।”

28. यह न्यायालय पाता है कि 'पुलिस जवाबदेही समिति' तंत्र से संबंधित उपर्युक्त वैधानिक प्रावधान विभिन्न सुरक्षा उपायों के कमजोर पड़ने से चिह्नित हैं, जिन्हें प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में निर्धारित किया गया था। उक्त वैधानिक प्रावधान दोनों स्तरों पर 'पुलिस जवाबदेही समितियों' की संरचना, चयन की विधि और सिफारिशों की (गैर-)बाध्यकारी प्रकृति के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों से विचलन प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेखांकित 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' तंत्र के विशिष्ट पहलू, जिनका राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 के तहत 'पुलिस जवाबदेही समिति' तंत्र से संबंधित प्रावधानों में उल्लंघन किया गया है, इस प्रकार हैं:

28.1. संरचना: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रमुख माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, जबकि जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण का नेतृत्व सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश करेंगे। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में "सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य विभाग के अधिकारियों या नागरिक समाज के सदस्यों में से सदस्य शामिल होंगे।" इसके विपरीत, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 63 और 66 में कहा गया है कि राज्य और जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों में चार "स्वतंत्र सदस्यों के रूप में सार्वजनिक व्यवहार में अनुभव वाले और मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता का विश्वसनीय रिकॉर्ड रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति" शामिल होंगे; और सदस्य-सचिव के रूप में निर्दिष्ट रैंक का एक पुलिस अधिकारी शामिल होगा। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 63 और 66 राज्य सरकार को किसी भी 'स्वतंत्र सदस्य'

को राज्य या जिला स्तर पर संबंधित पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का अधिकार देती है।

28.2. चयन की विधि: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकार राज्य मानवाधिकार आयोग, लोक द्वारा तैयार नामों के पैनल में से राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। आयुक्त, या राज्य लोक सेवा आयोग। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार को पुलिस शिकायत प्राधिकरणों के प्रमुखों का चयन क्रमशः मुख्य न्यायाधीश (राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में) द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल से करना आवश्यक है; और मुख्य न्यायाधीश या इस उद्देश्य के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (जिला स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण के संबंध में) द्वारा। इसके विपरीत, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 63 और 66 राज्य सरकार को राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस जवाबदेही समितियों' के सदस्यों को नियुक्त करने के लिए पूर्ण अधिकार प्रदान करती है, बिना निर्दिष्ट न्यायिक अधिकारियों/चौथी शाखा के संस्थानों द्वारा नामों के पैनल की पूर्व तैयारी के, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकाश सिंह (सुप्रा) में निर्देशित किया था। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 68(2) के तहत, राज्य सरकार के पास राज्य और जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों से किसी भी 'स्वतंत्र सदस्य' को हटाने की शक्ति है, जो राज्य सरकार के इस आकलन पर आधारित है कि क्या और कब संबंधित सदस्य "एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहता है"।

28.3. सिफारिशों की प्रकृति: प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, दोनों स्तरों पर पुलिस शिकायत प्राधिकारियों को किसी दोषी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को बाध्यकारी सिफारिशें जारी करने का अधिकार होगा। इसके विपरीत, राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 राज्य और जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों को बाध्यकारी सिफारिशें करने की शक्ति नहीं देता है। इस संबंध में, अधिनियम की धारा 64(सी) राज्य पुलिस जवाबदेही समिति को केवल राज्य सरकार को सिफारिशें करने का अधिकार देती है। इसके अलावा, जिला स्तर पर पुलिस जवाबदेही समितियों के मामले में, अधिनियम की धारा 67(ए) का प्रावधान संबंधित पुलिस जवाबदेही समिति की सिफारिशों को संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय के अधीन करता है।

29. यह न्यायालय 'पुलिस जवाबदेही समिति' तंत्र से संबंधित मौजूदा वैधानिक प्रावधानों को प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों में निहित दृष्टिकोण को प्रभावी बनाने के लिए अपर्याप्त मानता है। राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 राज्य सरकार को राज्य और जिला पुलिस जवाबदेही समितियों के सदस्यों को चुनने या हटाने और राजनीतिक विचारों के आधार पर इन संस्थाओं की सिफारिशों को अपनाने या खारिज करने के लिए एक आभासी पूर्णाधिकार प्रदान करता है। इसलिए, राज्य और जिला स्तर पर मौजूदा 'पुलिस जवाबदेही समिति' तंत्र प्रभावी रूप से एक आंतरिक/आंतरिक तंत्र है जो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों पर निर्णय लेने की शक्तियों को राज्य सरकार के पास केंद्रित करता है, और इस प्रकार पुलिस पर बाहरी प्रभाव के बारे में चिंताओं को दूर करने में विफल रहता है जो प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का आधार है। परिणामस्वरूप, यह न्यायालय 'पुलिस जवाबदेही समिति' तंत्र को राज्य में पुलिस संस्कृति और कार्यप्रणाली को औचित्यपूर्ण संस्कृति में बदलने में असमर्थ मानता है, जहाँ पुलिस अधिकारी संवैधानिक सिद्धांतों और मूल्यों के अनुसार अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और इन सिद्धांतों और मूल्यों की कसौटी पर जनता द्वारा और जनता के प्रति जवाबदेह ठहराए जा सकते हैं। तदनुसार, यह न्यायालय राजस्थान राज्य के लिए यह आवश्यक मानता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह (सुप्रा) के निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार नियुक्त और गठित किए जाएँ।

निर्देशः

29. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के साथ-साथ बीएनएसएस 2023 की धारा 528 (सीआरपीसी 1973 की धारा 482 के अनुरूप) के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के प्रति सचेत है, ताकि उन व्यक्तिगत याचिकाओं के अंतर्निहित तथ्यात्मक परिदृश्यों का सटीक और व्यापक दृष्टिकोण विकसित किया जा सके, जिनमें याचिकाकर्ता(यों) द्वारा पुलिस सुरक्षा से संबंधित निर्देशों की प्रार्थना की जाती है। उदाहरण के लिए, जहां ऐसी याचिकाएं विवाहित/निकट संबंध में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर की जाती हैं , उनमें अक्सर उन पक्षों की आयु और नागरिकता सहित तथ्यों के विवादित और/या जटिल आकलन शामिल होते हैं, जो बड़ी हुई पुलिस सुरक्षा चाहते हैं; संबंधित पक्षों द्वारा सामना किए जाने वाले खतरे की प्रकृति और सीमा; क्या संबंधित पक्षों, विशेष रूप से संबंधित महिलाओं ने विवाह/निकट संबंध में प्रवेश करने में स्वतंत्र सहमति का प्रयोग किया है; और संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से लागू किए जाने वाले सटीक उपाय यह

सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित जोड़े के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित हैं। यह न्यायालय संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को व्यक्तिगत मामलों से संबंधित तथ्यात्मक परिदृश्यों का समग्र और सटीक दृष्टिकोण प्राप्त करने, साथ ही संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपायों का पता लगाने और उन्हें लागू करने के लिए अपेक्षाकृत रूप से सक्षम मानता है। फिर भी, यह न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ निर्देश जारी करना अनिवार्य मानता है कि संबंधित पुलिस प्राधिकारी संबंधित व्यक्तियों के प्रति अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का पर्याप्त रूप से निर्वहन करें; और यह कि संबंधित पुलिस अधिकारी उक्त दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी हों।

30. तदनुसार, इन तथ्यों पर संचयी विचार करने के बाद कि वयस्कता की आयु प्राप्त कर चुके प्रत्येक व्यक्ति को अपने साथी/जीवनसाथी को चुनने के लिए संवैधानिक रूप से संरक्षित व्यक्तिगत स्वायत्तता प्राप्त है; कि राज्य, और विशेष रूप से पुलिस प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक और वैधानिक दायित्व वहन करते हैं कि संबंधित जोड़े अन्य सामाजिक अभिनेताओं या समूहों द्वारा लगाए गए अतिरिक्त-कानूनी बाध्यताओं के बिना ऐसे अंतरंग व्यक्तिगत विकल्प बनाने में सक्षम हैं; और लता सिंह (सुप्रा), शक्ति वाहिनी (सुप्रा) के निर्णयों में प्रतिपादित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भरोसा करते हुए, और प्रकाश सिंह (सुप्रा), यह न्यायालय यह उचित समझता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि विवाहित/निकट संबंध में रहने वाले जोड़े अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुरक्षा से संबंधित पर्याप्त उपायों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हैं, निम्नलिखित प्रक्रिया को रेखांकित किया जाए। निम्नलिखित निर्देश राज्य सरकार के मौजूदा संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों के राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 29 के तहत दायित्वों की उचित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार किए गए हैं। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि इस निर्णय के पैराग्राफ 31 में विस्तृत कारणों से, निम्नलिखित निर्देश आम तौर पर उन व्यक्तियों पर लागू होंगे जो अन्य सामाजिक अभिनेताओं या समूहों (इसके बाद 'आवेदक') से अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिए अतिरिक्त-कानूनी खतरों के कारण अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों के कार्यान्वयन की मांग करते हैं। इसलिए, निम्नलिखित निर्देश उन संबंधित व्यक्तियों तक विस्तारित होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे, जिन्हें अपने साथी/जीवनसाथी की पसंद के कारण ऐसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

30.1 आवेदक/आवेदक संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिन्हें ऐसे अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने हेतु नोडल अधिकारी के रूप में नामित

किया गया है। इस संबंध में, राज्य सरकार और राजस्थान भर के पुलिस अधिकारी आवेदक/आवेदकों द्वारा ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट और प्रचारित करेंगे। आवेदक/आवेदकों को संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष भौतिक रूप से/व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाने के अलावा, राज्य सरकार से एक ऑनलाइन तंत्र विकसित करने की अपेक्षा की जाती है जहाँ आवेदक/आवेदक उपर्युक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकें और उन पर होने वाली कार्यवाही के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकें।

30.2 यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि बीएनएसएस 2023 की धारा 173 में प्रतिपादित 'शून्य एफआईआर' की अवधारणा के अनुसार, मात्र क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव उपर्युक्त अभ्यावेदन प्राप्त करने वाले नोडल अधिकारी के लिए उसे खारिज करने का आधार नहीं होगा। इसके बजाय, संबंधित नोडल अधिकारी, जो अभ्यावेदन प्राप्त करता है, (i) यह सुनिश्चित करेगा कि पूर्वोक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने के 3 दिनों की ऊपरी सीमा के भीतर, आवेदक संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दायर करने में सक्षम है, जिसके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है; और (ii) संबंधित नोडल अधिकारी के साथ समन्वय करेगा, जिसके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदक(ओं) को आवश्यक होने पर अंतरिम संरक्षण प्राप्त हो, और अभ्यावेदन पर कानून के अनुसार विचार किया जाए और उस पर निर्णय लिया जाए। बीएनएसएस 2023 के अंतर्गत 'शून्य एफआईआर' की अवधारणा से संबंधित प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“धारा 173 - संज्ञेय मामलों में सूचना

(1) किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक सूचना, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी और यदि दी जाए-

(i) मौखिक रूप से, वह उसके द्वारा या उसके निर्देशन में लिखित रूप में दी जाएगी और सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी; और ऐसी प्रत्येक सूचना, चाहे लिखित रूप में दी गई हो या पूर्वोक्त रूप से लिखित रूप में दी गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी;

(ii) इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिन के भीतर हस्ताक्षर किए जाने पर उसके द्वारा अभिलेख पर लिया जाएगा, और उसका सार ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्ररूप में दर्ज किया जाएगा जैसा राज्य सरकार नियमों द्वारा इस संबंध में निर्धारित करे: ...”

30.3 अनुच्छेद 30.1 और 30.2 में निर्दिष्ट आवेदक(ओं) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, संबंधित नोडल अधिकारी, जिसके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है, आवेदक(ओं) को उपस्थिति और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। आवेदक संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुन सकता है। संबंधित नोडल अधिकारी के समक्ष कार्यवाही, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2021) 1 एससीसी 184** में रिपोर्ट किए गए परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह एवं अन्य मामले में दिए गए निर्देशों के अनुसार, संबंधित पुलिस स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से विधिवत रिकॉर्ड की जाएगी।

30.4 अनुच्छेद 30.1 और 30.2 में निर्दिष्ट आवेदक(ओं) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, अनुच्छेद 30.3 में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक(ओं) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सुरक्षा के अपेक्षित उपाय, यदि कोई हों, लागू किए जाएँ। इसके अतिरिक्त, संबंधित नोडल अधिकारी अभ्यावेदन पर विचार करेंगे, आवेदक(ओं) को उपस्थित होने और सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे, और अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों की ऊपरी सीमा के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन पर निर्णय लेंगे। जहाँ संबंधित नोडल अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक(ओं) को उनकी सुरक्षा के लिए दावे के अनुसार, अतिरिक्त-कानूनी खतरों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ आवश्यकतानुसार निम्नलिखित उपाय लागू किए जाएँगे:

30.4.1 संबंधित नोडल अधिकारी आवेदक(ओं) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ पुलिसकर्मी तैनात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ आवेदक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अपने जीवनसाथी/जीवनसाथी के चयन के कारण अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कानूनी खतरों का सामना करना पड़ता है, वहाँ यदि आवेदक चाहें तो संबंधित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आवेदक शक्ति वाहिनी (सुप्रा) के निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत गठित आश्रय गृहों में से किसी एक में सुरक्षित निवास प्राप्त करें। यदि आवेदक(ओं) की इच्छा के बावजूद इनमें से कोई एक/दोनों उपाय लागू नहीं किए जाते हैं, तो इसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा और आवेदक(ओं) को सूचित किया जाएगा।

30.4.2 जहाँ जिन व्यक्तियों से अतिरिक्त कानूनी खतरों की आशंका है, वे बड़ी हुई पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाले जोड़े के परिवार के सदस्य हैं, संबंधित नोडल अधिकारी संबंधित जोड़े और ऐसे परिवार के सदस्यों के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही से पहले, संबंधित नोडल अधिकारी संबंधित परिवार के सदस्यों को जोड़े के अपने साथी/जीवनसाथी चुनने के

संवैधानिक अधिकारों के बारे में विधिवत सूचित करेगा। इसके अलावा, संबंधित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित जोड़े, विशेष रूप से वह महिला जो अपनी स्वायत्तता का प्रयोग करने के कारण अतिरिक्त कानूनी खतरों की आशंका करती है, को उनके संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराया जाए और मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान परिवार के सदस्यों द्वारा उन पर कोई दबाव न डाला जाए। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि पूर्वोक्त मध्यस्थता कार्यवाही अनुच्छेद 30.4 और 30.4.1 में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के बाद ही आयोजित की जाएगी, न कि उसके एवज में।

30.5 जहां आवेदक इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दायर किए गए अभ्यावेदन के संबंध में संबंधित नोडल अधिकारी के निर्णय/निष्क्रियता से व्यथित है, तो आवेदक निम्नलिखित उपायों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा:

30.5.1 आवेदक /आवेदक संबंधित पुलिस अधीक्षक को उपयुक्त अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। संबंधित पुलिस अधीक्षक ऐसे अभ्यावेदन पर, अभ्यावेदन प्राप्त होने की अधिकतम 3 दिनों की सीमा के भीतर विचार कर निर्णय लेंगे।

30.5.2 जहां आवेदक अनुच्छेद 30.5.1 में निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व के संबंध में संबंधित पुलिस अधीक्षक के निर्णय/निष्क्रियता से व्यथित है, आवेदक पुलिस शिकायत प्राधिकरण तंत्र के उचित स्तर के समक्ष उचित शिकायत दर्ज कर सकता है, जैसा कि प्रकाश सिंह (सुप्रा) के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में गठित किया गया है। ऐसी शिकायत के माध्यम से, आवेदक संबंधित नोडल अधिकारी और/या पुलिस अधीक्षक का नाम लेकर अभियोग लगा सकता है, जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने संवैधानिक और वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहे, इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार आवेदक द्वारा दायर प्रतिनिधित्व पर विचार और निपटान नहीं करके, और/या आवेदक के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन में अन्य सामाजिक अभिनेताओं या समूहों के साथ मिलीभगत करके। जहां संबंधित पुलिस शिकायत प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संबंधित नोडल अधिकारी(यों) और/या संबंधित पुलिस अधीक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित हो गए हैं, वहां वह संबंधित अधिकारी(यों) के खिलाफ कानून के अनुसार उचित आपराधिक और/या सिविल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए उचित बाध्यकारी सिफारिशें जारी करेगा। इस संबंध में, यह न्यायालय राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह प्रकाश सिंह (सुप्रा) के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, राजस्थान राज्य में राज्य और जिला स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' की नियुक्ति और गठन के लिए आवश्यक कदम उठाए, ताकि राज्य

और जिला स्तर पर 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' इस फैसले की तारीख से एक महीने के भीतर अपना काम करना शुरू कर दें। यदि राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहती है, तो यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस न्यायालय के निर्देशों के माध्यम से 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के दोनों स्तरों की नियुक्ति और गठन किया जाए। ऐसे निर्देश यह सुनिश्चित करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह (सुप्रा) में जारी निर्देश राजस्थान राज्य में प्रभावी हों, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा उक्त निर्देशों को लागू करने में 18 वर्षों का अस्पष्ट विलंब हुआ है।

30.6 जहां आवेदक अनुच्छेद 30.5.2 में निर्दिष्ट शिकायत के अनुसरण में संबंधित पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित है, या जहां संबंधित पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही उचित समय के भीतर समाप्त नहीं होती है, आवेदक को बाध्यकारी कारणों से और कानून के अनुसार भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करने की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते समय, आवेदक याचिका में उचित दलीलें और एक फुटनोट शामिल करेगा जिसमें उन विवरणों का खुलासा किया जाएगा जो इंगित करते हैं कि इस निर्णय के अनुच्छेद 30.1 से 30.5.2 के अनुसार संबंधित नोडल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उपयुक्त स्तर के समक्ष उचित अभ्यावेदन/शिकायत दर्ज करने के माध्यम से वैकल्पिक प्रभावोत्पादक उपायों का पहले ही लाभ उठाया जा चुका है।

30.7. निम्नलिखित फ्लोचार्ट इस निर्णय के पैराग्राफ 30.1 से 30.6 के अंतर्गत वर्णित तंत्र को दर्शाता है:

चरण 1: आवेदक को अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं/समूहों की ओर से अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए अतिरिक्त कानूनी खतरों की आशंका है।

चरण 2: आवेदक/आवेदक किसी निर्दिष्ट नोडल अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र हो भी सकता है और नहीं भी। [यदि जिस नोडल अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, उसके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो संबंधित नोडल अधिकारी इस निर्णय के अनुच्छेद 30.2 में निर्दिष्ट कदम उठाएंगे।]

चरण 3: मामले पर क्षेत्रीय अधिकार रखने वाले संबंधित नोडल अधिकारी, यदि आवश्यक हो, तो तत्काल आधार पर आवेदक(ओं) के लिए अंतरिम सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करेंगे।

चरण 4: मामले पर क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला संबंधित नोडल अधिकारी अभ्यावेदन पर विचार करेगा, आवेदक को व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, तथा अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 7 दिनों की ऊपरी सीमा के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा।

चरण 5: यदि चरण 2 से 4 में निर्दिष्ट संबंधित नोडल अधिकारी के निर्णय/निष्क्रियता से व्यथित हैं, तो आवेदक संबंधित पुलिस अधीक्षक के समक्ष अभ्यावेदन दायर कर सकते हैं।

चरण 6: संबंधित पुलिस अधीक्षक अभ्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से 3 दिन की ऊपरी सीमा के भीतर कानून के अनुसार अभ्यावेदन पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे।

चरण 7: यदि संबंधित पुलिस अधीक्षक के निर्णय/निष्क्रियता से व्यथित हैं, तो आवेदक 'पुलिस शिकायत प्राधिकरण' के उचित स्तर के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

चरण 8: जहां (और केवल जहां) आवेदक संबंधित पुलिस शिकायत प्राधिकरण के निर्णय से व्यथित है, या संबंधित पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही उचित समयावधि के भीतर समाप्त नहीं हुई है, आवेदक बाध्यकारी कारणों से और कानून के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान कर सकता है।

30.8. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के लिए अभ्यावेदनों पर विचार करने और उनके निपटारे के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं और तंत्रों को उपयुक्त 'मानक संचालन प्रक्रिया' (SoP) के प्रख्यापन के माध्यम से इस निर्णय के पैराग्राफ 30.1 से 30.5.1 और साथ ही 30.7 में निर्धारित निर्देशों के अनुरूप लाया जाए। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि उपर्युक्त SoP में , अन्य बातों के साथ-साथ, इस निर्णय के पैराग्राफ 30.1 में निर्दिष्ट ऑनलाइन तंत्र का विवरण, साथ ही कुछ व्हाट्सएप /हेल्पलाइन नंबर और एक निर्दिष्ट ईमेल आईडी निर्दिष्ट की जाएगी, जहां संबंधित व्यक्ति जो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं, अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त ऑनलाइन तंत्र और व्हाट्सएप / हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी हर समय प्रभावी और कार्यात्मक हों, और संबंधित व्यक्तियों के लिए सुलभ हों राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त एसओपी प्रत्येक पुलिस

स्टेशन पर पुलिस अधिकारियों और आगंतुकों के लिए सुलभ हो, और समाचार पत्रों में प्रकाशन, उपयुक्त सोशल मीडिया हैंडल आदि के माध्यम से यथासंभव व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए।

31. इस मामले से विदा लेने से पहले, यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 14 और 21 के तहत संवैधानिक गारंटी के तहत, दंपतियों के अलावा, उन व्यक्तियों/समूहों के मामले में पुलिस सुरक्षा बढ़ाने के उपायों के कार्यान्वयन की आवश्यकता हो सकती है, जो मौजूदा सामाजिक ढाँचों की अवहेलना करते हुए अपनी व्यक्तिगत स्वायत्तता का दावा करते हैं और इस प्रकार अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए क़ानून-से-बाहर के खतरों की आशंका करते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसी सुरक्षा उन महिलाओं के मामले में आवश्यक हो सकती है, जिन्हें परिवार के कहने पर विवाह न करने के कारण अपने परिवार के सदस्यों से क़ानून-से-बाहर हिंसा का ख़तरा होता है। ऐसी सुरक्षा उन व्यक्तियों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के मामले में भी आवश्यक हो सकती है, जो इलाके के प्रभावशाली राजनीतिक/सामाजिक कर्ताओं द्वारा की गई क़ानून-से-बाहर की आर्थिक माँगों को मानने से इनकार करते हैं। यह न्यायालय स्पष्ट करता है कि इस निर्णय के पैराग्राफ 30 से 30.8 में निर्दिष्ट निर्देश और प्रक्रिया, आवेदक(ओं) के जीवन और स्वतंत्रता के लिए संभावित खतरों के संबंध में, युगलों के अलावा आवेदक(ओं) द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष दायर अभ्यावेदनों/शिकायतों पर यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी।

32. रजिस्ट्रार (न्यायिक) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान मामले को 9 सितंबर 2024 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ताकि उचित 'मानक संचालन प्रक्रिया' (एसओपी) के प्रचार के संबंध में इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, और प्रकाश सिंह (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण की नियुक्ति और गठन किया जा सके।

33. इस न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस निर्णय की एक प्रति राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव को भेजी जाए।

34. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2, इस निर्णय की तिथि से 7 दिनों की ऊपरी सीमा के भीतर, इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, एक नामित नोडल अधिकारी के समक्ष उपयुक्त अभ्यावेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इस मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र रखने वाले संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दाखिल अभ्यावेदन (यदि कोई हो) पर विचार करने और उसका निपटारा करने तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए, प्रतिवादी

संख्या 2 से 5 को यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित उपाय लागू करने का निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 के जीवन और स्वतंत्रता को प्रतिवादी संख्या 6 से 10 सहित अन्य सामाजिक कर्ताओं या समूहों से अतिरिक्त-कानूनी खतरों से सुरक्षित रखा जाए। 35. उपरोक्त निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निपटाए जाते हैं।

(समीर जैन), जे

पूजा /11

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी